अनुषंगी उद्योगों का स्थापित किया जाना

561. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे भारी उद्योगों की संख्या कितनी है और इन उद्योगों में अब तक कितनी पूंजी का निवेश किया गया है और उन राज्यों में भारी उद्योगों के क्षेत्र में प्राइवेट सैक्टर की स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन भारी उद्योगों के लघु तथा मध्यम दर्जे के अनुषंगी उद्योग अधिकाधिक संख्या में स्थापित करने तथा जापान की तरह भारी उद्योगों के लिये अपेक्षित 90 प्रतिशत मदों का इन्हीं एककों में उत्पादन करने की कोई योजना है; और

(ग) बिहार में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्योग होने के बावजूद इस राज्य में अनुषंगी उद्योगों की दशा इतनी दयनीय होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में लोक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

562. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन के मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन्हीं कारणों से इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा की गई अपील के बावजूद हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम को पिछले 18 वर्षों में एक बार भी कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ग) मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, संस्थानों तथा कम्पनियों को चालू वर्ष के लिये हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में वार्षिक कार्यक्रम किस-किस तारीख को भेजे गये और इन कार्यालयों में उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(घ) इस वर्ष समूचे वार्षिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिये क्या व्यवस्थायें की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 27 जन, 1984 को किया गया था तथा पिछले 3 वर्षों अर्थात 1984–86 तक इसकी चार बैठकें की गई हैं। अगली बैठक 27 मार्च, 1987 को बुलाई गई है। यद्यपि समिति की प्रति वर्ष निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जाते हैं फिर भी अभी तक ऐसा कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) 1986–87 के वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां मंत्रालय के चारों विभागों अर्थात् औद्योगिक विकास विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, सरकारी उद्यम विभाग तथा रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा क्रमशः 28–7–86, 25–8–86, 17–9–86 तथा 5–9–86 को सम्बधित अधिकारियों/कार्यालयों को सूचना एवं कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई थीं।

कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में बराबर कार्यवाही की जा रही है। पत्राचार में निर्धारित प्रतिशत प्राप्त करने, अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने, कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करने; प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने;